पुर से लखनऊ और लखनऊ से बम्बई रेल की छतों पर हजारों की संख्या में बैठकर लोग आते और जाते हैं। दुर्घटना की चिंता न करके अपने पेट की पीड़ा बुझाने के लिए अपनी बलि भी दे देते हैं। 1971 से रेल सलाहकार समिति एवं रेलवे मन्त्रालय की मांगों की चर्चा के समय में ही नहीं, सदन के अन्य मेरे दोस्त भी गोरखपुर से बम्बई के लिए सीधी 22 डिब्बों की रेलगाड़ी प्रतिदिन चलाने की एक स्वर में मांग करते रहे हैं। गोरखपुर से लखनऊ की रेल लाईन को ब्राडगेज हुए लगभग दो वर्ष हो गए हैं परन्तु आज तक गोरखपुर से बम्बई के लिए 22 डिब्बों की गाड़ी नहीं चलाई गई, रेलवे बोर्ड अब यह तर्क दे रहा है कि बम्बई में गोरखपुर की ट्रेन को रोकने के लिए जगह ही नहीं है।

मैं प्रधानमंत्री जी एवं रेल मन्त्री जी से यह विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि गोरखपुर से बम्बई के लिए 22 डिब्बों की सीधी ट्रेन चलाने की व्यवस्था करें, जिससे शांतिप्रिय पूर्वी उ० प्र० की जनता को कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर न होना पड़े कि रेल व्यवस्था अस्त-व्यस्त ही हो जाए।

(viii) Proposed of 15 percent production cut by Jute Mills in West Bengal

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Sir, in west Bengal, the private jute mill owners have come out with a proposal of 15% production cut in Jute Mills on the plea of so-called shortage of jute fibre. This plea is totally baseless and the proposed cut is intended to lay off the workers as well as to depress the price of the new jute crop which will arrive in the market after a few months. This also is intended to wrest further concessions from the Government. The trade union including AITUC and peasant organisation as well as the Government of West Bengal have sharply reacted against this proposal.

I request the Ministry of Commerce of the Government of India to take up this question with IJMA and see to it that this motivated harmful proposal cannot be given effect to.

(xi) Arrangement of gram and payment of its price to farmers

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कृषि उत्पादन की समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की जा रही है।

केन्द्र सरकार ने चने का समर्थन मूल्य 235 रु० प्रति क्विंटल घोषित किया है, किन्तु मध्य प्रदेश में किसानों से 225 रु० प्रति क्विंटल के भाव से चना खरीदा गया है। इतना ही नहीं तो सरकारी खरीद की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण किसानों को चना कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जो चना सरकारी निकायों के लिए खरीदा जा रहा है, उसका भुगतान किसानों को नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में करोड़ों-रुपयों का भुगतान किसानों को किया जाना है, जिसमें उज्जैन जिले का ही करीब एक करोड़ रुपया किसानों को भुगतान करना बकाया है।

कृषि उत्पादनों के भुगतान में अप्रत्याशित विलम्ब के कारण किसान परेशान है तथा अभी की बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक प्रभावित हुई है। कृषकों की ऐसी विषम स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सरकार कृषि उत्पादनों की खरीद और भुगतान का तत्काल पर्याप्त प्रबन्ध करे।

13.10 hrs.

FINANCE BILL—1983—CONTD :

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, let us take up the next item. The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Pranab Kumar Mukherjee on the 27th April, 1983, namely:—

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1983-84, be taken into consideration."

Mr. Sontosh Mohan Dev may continue his speech.